वर्ष : 12 > अंक : 10 RNI No. RAJHIN/2015/75198 मूल्य: 2 रुपए > पृष्ठ : 04

चुप्पी तोड़

पाक्षिक समाचार पत्र

www.chuppitod.com
email: info.chuppitod@gmail.com

राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली से प्रसारित

बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

16 जून, 2026

www.youtube.com/@chuppitod Instagram.com/chuppi.tod chuppitod.blogspot.com facebook.com/chuppiTod twitter.com/chuppitod?s=B2M1i8a8f... t.me/chuppitod

नीमराना-बहरोड़ को जल्द मिलेगा मेट्रो का तोहफा

दिल्ली-अलवर रैपिड रेल परियोजना को मिली रफ्तार

चुप्पी तोड़
नई दिल्ली/बहरोड़। राजस्थान के औद्योगिक हब नीमराना-बहरोड़ और आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी (शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़)-अलवर नमो भारत परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। करीब 164 किलोमीटर लंबे इस हाई-स्पीड कॉरिडोर के शुरू होने के बाद दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी, बावल, नीमराना, बहरोड़, सोतानाला और अलवर के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी तथा क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशनद्वारा विकसित की जा रही यह परियोजना केंद्र सरकार तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों की संयुक्त पहल है। एनसीआरटीसी की आधिकारिक योजना के अनुसार दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर कॉरिडोर नमो भारत नेटवर्क की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है।

नीमराना-बहरोड़ को होगा सबसे बड़ा लाभ: जापानी और अन्य विदेशी निवेश के कारण नीमराना-बहरोड़ क्षेत्र पहले ही देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल हो चुका है। नमो भारत कॉरिडोर शुरू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर से इन क्षेत्रों की दूरी और समय दोनों कम हो जाएंगे। उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और नए निवेश का लाभ मिलेगा।

प्रस्तावित स्टेशन

इस कॉरिडोर पर लगभग 21 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें प्रमुख स्टेशन शामिल हैं:

- सराय काले खां
- INA
- मुनिरका
- एयरोसिटी
- साइबर सिटी/ गुरुग्राम क्षेत्र
- राजीव चौक
- खेड़की दौला
- मानेसर
- पंचगांव
- बिलासपुर चौक
- धारूहेड़ा
- MBIR
- रेवाड़ी
- बावल
- शाहजहांपुर
- नीमराना
- बहरोड़
- सोतानाला
- खैरथल
- अलवर

हालांकि स्टेशन संख्या और नामों में भविष्य में बदलाव संभव हैं।

93.5 किलोमीटर रूट का सर्वे पूरा

परियोजना की प्रगति भी तेजी से आगे बढ़ रही है। गुरुग्राम साइबर सिटी से बावल तक लगभग 93.5 किलोमीटर रूट का विस्तृत सर्वे पूरा किया जा चुका है। विभिन्न स्थानों पर सॉयल टेस्टिंग की जा चुकी है तथा बिजली, पानी और अन्य यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए आवश्यक स्थानों की पहचान भी कर ली गई है। भूमि संबंधी अंतिम मंजूरियों के बाद निर्माण कार्य में और तेजी आने की उम्मीद है।

164 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर दौड़ेगी 160 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार

प्रस्तावित कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गुरुग्राम, मानेसर, पंचगांव, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, बावल, शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड़, सोतानाला, खैरथल होते हुए अलवर तक पहुंचेगा। नमो भारत ट्रेनें लगभग 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से संचालित होंगी। परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली से अलवर की यात्रा लगभग दो घंटे के भीतर पूरी होने का अनुमान है।

रेवाड़ी को झटका, पंचगांव-मानेसर को फायदा

डिपो के धारूहेड़ा से पंचगांव स्थानांतरित होने से रेवाड़ी जिले को मिलने वाले संभावित निवेश, रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा गुरुग्राम-मानेसर क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो सकता है। वहीं पंचगांव, मानेसर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक, आवासीय और कमर्शियल विकास को नई गति मिलने की संभावना है।

पंचगांव में बनेगा मेन डिपो, परियोजना में बड़ा बदलाव

परियोजना से जुड़ा बड़ा बदलाव डिपो की लोकेशन को लेकर सामने आया है। पहले मुख्य डिपो धारूहेड़ा में प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे गुरुग्राम जिले के पंचगांव क्षेत्र में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। एनसीआरटीसी ने डिपो के लिए लगभग 99 एकड़ भूमि की मांग की है तथा गुरुग्राम प्रशासन नई साइट का प्रस्ताव सरकार को भेज चुका है। सूत्रों के अनुसार डिपो केवल ट्रेनों की पार्किंग का स्थान नहीं होगा, बल्कि पूरे कॉरिडोर का संचालन, 24 घंटे निगरानी, तकनीकी परीक्षण और सेंट्रल कंट्रोल सेंटर भी यहीं स्थापित किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजना शुरू होने के बाद-

- औद्योगिक निवेश में वृद्धि होगी,
- रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे,
- रियल एस्टेट बाजार को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा,
- दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान के बीच दैनिक आवागमन आसान होगा,
- गुरुग्राम और दिल्ली में कार्यरत लोग नीमराना-बहरोड़ से प्रतिदिन अप-डाउन कर सकेंगे।

मेरठ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा विकास

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की सफलता के बाद अब दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर कॉरिडोर को उसी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। विशेषज्ञ इसे दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान के बीच आर्थिक एकीकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक मान रहे हैं।

गुर्जर, डांगी और पूनिया निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित

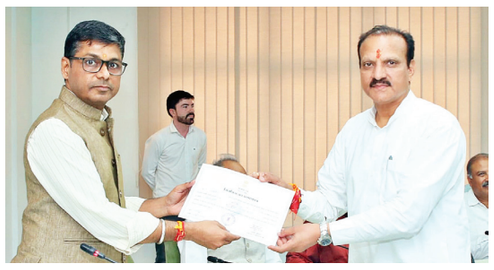

भाजपा ने अलका गुर्जर और सतीश पूनिया, कांग्रेस ने नीरज डांगी पर जताया भरोसा

चुप्पी तोड़
जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव-2026 में भारतीय जनता पार्टी की डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पूनिया तथा कांग्रेस के नीरज डांगी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। नाम वापसी की अंतिम तिथि गुजरने के बाद विधानसभा में राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी भारत भूषण शर्मा ने तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की और उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया और पूर्व विधायक डॉ. अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत होने के कारण दोनों की जीत पहले से ही लगभग तय मानी जा रही थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन के वरिष्ठ नेता सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू तथा अन्य संभावित नामों को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया।

वहीं कांग्रेस ने अपने मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी पर दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें पुनः उम्मीदवार बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले डांगी ने पार्टी नेतृत्व का विश्वास कायम रखा और निर्विरोध राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे।

राजस्थान से तीन सीटों के लिए केवल तीन वैध नामांकन होने के कारण मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी और सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। इस प्रकार गुर्जर, डांगी और पूनिया आगामी कार्यकाल के लिए राजस्थान का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करेंगे।

Rao Hotel

अच्छा, शुद्ध एवं ताजा खाने वालों की पहली पसंद

घर की गाय-भैसों के दूध, दही, छाछ व घी से निर्मित भोजन

स्वच्छ, साफ-सुधरा शांत व पारिवारिक माहौल

शौकीनों के लिए हरियाणवी हुक्का भी उपलब्ध

राव का खाना... आसान नहीं भुलाना...

राव होटल

अलवर-भिवाड़ी मेगा हाइवे, चिकानी, अलवर

9785122342

शहरी सेवा शिविर-2026: पट्टों से लेकर पेंशन व जनकल्याणकारी योजनाओं तक मिलेगा लाभ

शिविरों में मिलेंगी सेवाएं... समस्या समाधान

चुप्पी तोड़
कोटपूतली-बहरोड़। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविर-2026 के माध्यम से आमजन को विभिन्न सरकारी सेवाएं, वित्तीय रियायतें एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविरों में नागरिकों की लंबित समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के साथ नगर क्षेत्रों में स्वच्छता, सौंदर्यकरण एवं विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी।

शिविरों में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र, नामांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन, भवन निर्माण स्वीकृति, उपविभाजन-पुनर्गठन, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे तथा विभिन्न पट्टा प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही पेंशन, पीएम स्वनिधि, जनधन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा, मातृ वंदना, श्रम योगी मानधन एवं अन्य योजनाओं के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।

नगर क्षेत्रों में सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट सुधार, नालियों की सफाई, सीवर लाइन मरम्मत, पार्कों एवं सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यकरण तथा आवारा पशुओं के नियंत्रण जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बहरोड़ व कोटपूतली में वार्डवार शिविर: नगर परिषद बहरोड़ एवं कोटपूतली क्षेत्र में 12 जून से 24 जून तक वार्डवार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अटल सेवा केंद्रों एवं पंचायत भवनों पर भी विशेष शिविर लगाए जाएंगे। बहरोड़ में 24 जून से 10 जुलाई तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में तथा कोटपूतली क्षेत्र में 25 एवं 29 जून को पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित होंगे।

फॉलोअप शिविर भी होंगे आयोजित: बहरोड़ नगर परिषद क्षेत्र में 13 से 15 जुलाई तक फॉलोअप शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें पूर्व में प्राप्त लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों से निर्धारित तिथियों पर शिविरों में पहुंचकर अपने लंबित कार्यों का निस्तारण करवाने तथा राज्य सरकार की योजनाओं एवं रियायतों का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।

आमजन को मिलेंगी विशेष रियायतें

- बकाया लीज राशि जमा कराने पर ब्याज में 100% तक छूट।
- फ्री होल्ड एवं लीज मुक्ति प्रकरणों में 60% तक राहत।
- नामांतरण शुल्क में 50% छूट।
- भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन एवं पुनर्गठन शुल्क में विशेष रियायत।
- ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी आवासों की बकाया किस्तों पर ब्याज एवं शास्ति में 100% छूट।

ग्रामीण सेवा शिविरों में मिल रहा योजनाओं का त्वरित लाभ

चुप्पी तोड़
कोटपूतली-बहरोड़। राज्य सरकार की पहल पर आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर-2026 में ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविरों में पात्र व्यक्तियों के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के साथ ही सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण, खातों का शुद्धीकरण, सीमाज्ञान, भूमि आवंटन, जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा एवं राजीविका से संबंधित कार्य कर रहा है, जबकि पंचायती राज विभाग जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, पट्टे एवं स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच, टीकाकरण एवं पीएमजेएवाई कार्ड बनाए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग पशु स्वास्थ्य शिविर एवं बीमा सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। कृषि, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, श्रम, परिवहन, सहकारिता, शिक्षा, आयुर्वेद, सैनिक कल्याण, पीएचईडी, भू-जल, सार्वजनिक निर्माण एवं अन्य विभाग भी अपनी-अपनी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचा रहे हैं।

शिविरों की प्रमुख सेवाएं

- राजस्व एवं भूमि संबंधी प्रकरणों का निस्तारण
- जाति, मूल निवास व अन्य प्रमाण-पत्र जारी
- पीएम आवास, मनरेगा एवं राजीविका योजनाओं का लाभ
- स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण व आयुष्मान कार्ड
- पशु स्वास्थ्य शिविर एवं बीमा सुविधा
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार व छात्रवृत्ति कार्य

संपादकीय

आस्था के केंद्रों में पारदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक

राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में कथित अनियमितताओं से जुड़ी खबरें स्वाभाविक रूप से लोगों को विचलित करती हैं। यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या कुप्रबंधन सिद्ध होता है, तो यह केवल धन की हानि का मामला नहीं होगा, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास पर भी आघात माना जाएगा।

इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने दी जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप और तथ्य अलग-अलग होते हैं। इसलिए जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच करनी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके और दोषियों की जवाबदेही तय हो सके। साथ ही, यह मामला देश के सभी बड़े धार्मिक संस्थानों के लिए भी एक सीख है। श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान और चढ़ावा केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि विश्वास की पूंजी है। इसलिए उनके संग्रह, लेखा-जोखा, सुरक्षा और ऑडिट की व्यवस्था अत्याधुनिक एवं पारदर्शी होनी चाहिए। नियमित स्वतंत्र ऑडिट, डिजिटल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी निगरानी तथा सार्वजनिक जवाबदेही जैसी व्यवस्थाएं समय की आवश्यकता हैं।

यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उनका पद या प्रभाव कितना भी बड़ा क्यों न हो। वहीं यदि आरोप निराधार साबित होते हैं, तो इससे जुड़े भ्रम और आशंकाओं का भी पूरी स्पष्टता से निराकरण किया जाना चाहिए।

राम मंदिर राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उसकी गरिमा केवल भव्य निर्माण से नहीं, बल्कि उसके प्रबंधन की पारदर्शिता, जवाबदेही और श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा से भी सुनिश्चित होती है। इसलिए इस मामले में सबसे बड़ी आवश्यकता है—सत्य का निष्पक्ष अनावरण और जनता के विश्वास की पुनर्स्थापना।

...तो क्या इस चिट्ठी ने खोल दिया सतीश पूनिया का राज्यसभा का रास्ता?

मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार से राज्यसभा तक का सफर, क्या जाट राजनीति, संगठन के प्रति निष्ठा और हरियाणा विजय का मिला पुरस्कार?

शशी कुमार यादव, पत्रकार

जय जवान जय किसान

राजस्थान जाट महासभा

अध्यक्ष: राजाराम मील

कार्यालय: ए-1, पुराना पावर हाउस रोड, राम मन्दिर के पीछे, बनीपार्क, जयपुर -302006 फोन : 0141-2203799, Email: rajasthanjatmahasabha@gmail.com

क्रमांक: RJM/2805 दिनांक: 28-05-2026

श्री अमित शाह
गृहमंत्री भारत सरकार
नई दिल्ली।

महोदय,

जाट समुदाय हमारे देश की राजनीति में एक प्रभावशाली जनमत है लेकिन जाट समुदाय का इस बात पर रोष व नाराज़गी है कि बीजेपी एनडीए शासित भारत सरकार की कैबिनेट में गत 12 वर्षों से जाट समाज का एक भी केबीनेट मंत्री नहीं है।

हरियाणा उत्तरप्रदेश की बात छोड़ें अकेले राजस्थान में ही जाट समाज 16 लोकसभा सभा क्षेत्रों में प्रभाव रखता है और जीत हार भी तय करता है।

आपको याद होगा कि वर्ष 1999 में वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी लेकिन पुनः लोकसभा आम चुनाव मे राजस्थान का जाट समाज वाजपेयी जी की पहल पर बीजेपी के साथ आया और राजस्थान से लोक सभा में बीजेपी की 4 सीटों को बढ़ाकर 16 सीटें जीतवाई। 2014 व 2019 के आम चुनाव में भी राजस्थान से बीजेपी 25 में से 25 सीटें जीती जिसमें जाट समाज का भी पूरा योगदान रहा।

राजस्थान में जाट समाज की जनसंख्या 18% है यह जनसंख्या 16 लोक सभा क्षेत्रों में ही सघनता से होने की वजह से अपनी जनसंख्या के घनत्व के कारण जाट जाति चुनाव मे अधिक प्रभावशाली हो जाती है। जियोपोलिटिकल स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान से राज्य सभा में जाट समाज की कम से कम एक सीट का ओचित्य बनता है।

इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा सुझाव है कि कि किसी बाहरी व्यक्ति को राजस्थान से राज्यसभा में भेजने की बजाय राजस्थान से श्री सतीश पुनिया को राज्यसभा में भेजने का मौक़ा दिया जावे और उन्हें केन्द्रीय कैबिनेट में भी लिया जावे।

हम समझते हैं कि इससे जाट समाज की बीजेपी से निकटता बढ़ेगी और इससे बीजेपी को उतरी भारत के जाट बेल्ट में निर्णायक राजनीतिक लाभ मिलेगा।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय
(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

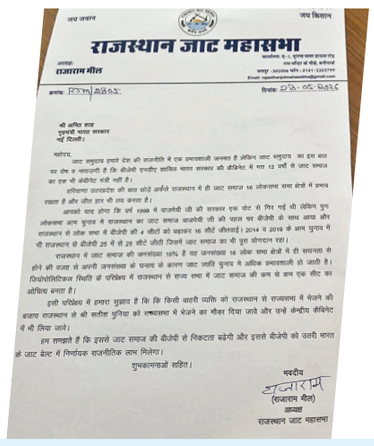

राजस्थान की राजनीति में सतीश पूनिया का राजनीतिक सफर पिछले कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। एक समय ऐसा था जब वे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ-साथ मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में गिने जाते थे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया गया और बाद में वे चुनाव भी हार गए। उस समय राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम थी कि पूनिया का राजनीतिक भविष्य अब सीमित हो सकता है। हालांकि राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और सतीश पूनिया इसका ताजा उदाहरण बनकर उभरे हैं। राजस्थान से राज्यसभा के लिए भाजपा उम्मीदवार घोषित होने के बाद वे एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं।

2023 में लगा था बड़ा झटकाः प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए सतीश पूनिया को भाजपा के संगठनात्मक चेहरे के रूप में देखा जाता था। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन हुआ और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनका नाम धीरे-धीरे पीछे चला गया। इसके बाद चुनावी हार ने उनके राजनीतिक सफर को और कठिन बना दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उस दौर में भाजपा के भीतर कई समीकरण काम कर रहे थे। वहीं कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे पार्टी की रणनीतिक पुनर्संरचना के रूप में भी देखा।

क्या जाट समाज की नाराजगी भी बनी वजह?ः इसी बीच राजस्थान जाट महासभा की ओर से लिखा गया एक पत्र चर्चा का विषय बन गया है। इस पत्र में राज्य की राजनीति में जाट समाज की भागीदारी और प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया गया है। पत्र में जाट समाज की जनसंख्या, विभिन्न लोकसभा सीटों पर उसके प्रभाव तथा भाजपा के प्रति उसके ऐतिहासिक समर्थन का उल्लेख किया गया है। महासभा ने सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजने और केंद्र में मंत्री बनाए जाने की मांग भी उठाई थी। इसके बाद जाट समाज के कुछ नेताओं ने दावा किया कि इस मांग ने भाजपा नेतृत्व पर प्रभाव डाला और पूनिया की दावेदारी मजबूत हुई। हालांकि भाजपा नेतृत्व की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है और यह स्पष्ट नहीं है कि टिकट देने के निर्णय में इस पत्र की कितनी भूमिका रही।

हरियाणा ने बदली राजनीतिक तस्वीर

वर्ष 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव सतीश पूनिया के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुए। भाजपा नेतृत्व ने उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। उस समय हरियाणा में जाट समाज की नाराजगी और राजनीतिक समीकरण भाजपा के लिए चुनौती बने हुए थे। भाजपा ने चुनाव में उल्लेखनीय सफलता हासिल की और राजनीतिक हलकों में इस जीत का कुछ श्रेय पूनिया की संगठनात्मक भूमिका को भी दिया गया। इसके बाद यह माना जाने लगा कि पार्टी नेतृत्व की नजर में उनका महत्व फिर बढ़ा है।

टिकट ने चौंकाया राजनीतिक गलियारों को

जब भाजपा ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर के नाम घोषित किए तो राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। क्योंकि संभावित उम्मीदवारों में कई बड़े नाम शामिल बताए जा रहे थे। ऐसे में पूनिया का चयन कई सवालों और विश्लेषणों को जन्म देने वाला रहा। कुछ राजनीतिक जानकार इसे हरियाणा में मिली सफलता का पुरस्कार मान रहे हैं, तो कुछ इसे संगठन के प्रति उनकी दीर्घकालिक निष्ठा का सम्मान बता रहे हैं। वहीं एक वर्ग इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संगठन के समर्थन से जोड़कर देख रहा है।

आगे क्या?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सतीश पूनिया का राज्यसभा पहुंचना उनके राजनीतिक पुनरुत्थान का अंतिम पड़ाव है या नई शुरुआत। क्या उन्हें भविष्य में केंद्र सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या भाजपा जाट समाज को साधने के लिए उन्हें और बड़ी भूमिका दे सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना निश्चित है कि 2023 में राजनीतिक रूप से कमजोर दिख रहे सतीश पूनिया ने 2026 में राज्यसभा पहुंचकर यह साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में वापसी के दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। राज्यसभा की यह जीत केवल एक संसदीय सीट नहीं, बल्कि सतीश पूनिया के राजनीतिक पुनरागमन की कहानी भी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि यह कहानी यहीं रुकती है या आगे किसी और बड़े अध्याय की ओर बढ़ती है।

असुरक्षा के भाव से क्यों ग्रस्त हैं गहलोत?

राजस्थान के गांधी, राजनीति के जादूगर एवं जननायक जैसी उपाधियों से नवाजे जाने वाले और तीन बार प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर संभाल चुके अशोक गहलोत आजकल काफी बेचैन दिख रहे हैं। हालांकि लगभग चालीस साल तक सत्ता के केंद्र में बने रहने के बाद अगर कोई नेता किसी भी पद चाहे वह सरकार में हो या पार्टी संगठन में नहीं रहे तो ऐसी स्थिति होना स्वाभाविक लगता है। फिर भी अशोक गहलोत की पीड़ा कुछ ज्यादा ही गहरी मालूम पड़ती है।

विधानसभा चुनाव में करारी हार के लगभग ढाई साल तक लगभग ' सुषुप्तावस्था' में रहे गहलोत फिलहाल ' अतिसक्रिय' दिख रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर प्रहार कर उन्हें कठघरे में खड़ा करना विपक्षी नेता के तौर पर उनका फर्ज है। उन्हें मुस्तैदी से ऐसा करना ही चाहिए परंतु वे अपनी पार्टी कांग्रेस के साथी नेताओं पर भी खीझ निकालने लगे हैं। अपनी वर्तमान दशा के लिए उन्हें दोषी ठहराना अस्वाभाविक है। खासतौर से बीते दिनों पुष्कर में राहुल गांधी के कथित दरकिनार और राज्यसभा चुनाव में टिकट न मिलने (चर्चा थी कि उन्हें राज्यसभा में भेजकर पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की कवायद चल रही थी) के बाद उनकी असहजता बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि गहलोत चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस संगठन में अहम भूमिका मिले या फिर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान एक बार फिर मिले ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में वह खुद अपने नेताओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट बांटे और पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर काबिज हुआ जा सके।

ध्यातव्य है कि अशोक गहलोत में कभी इतनी असुरक्षा की भावना नहीं देखी गई। उनकी असहजता के पीछे दो ही वजह मानी जाती हैं कि या तो उन्हें मन मुताबिक तवज्जो और पद पार्टी संगठन में नहीं मिल रहा अथवा पार्टी में उनके विरोधी या अन्य महत्वाकांक्षी नेता यथा सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जैसे नेताओं को आलाकमान अधिक महत्व दे रहा है।

अब देखना है कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी पहले की भांति अपनी धमक कायम रखते हुए वापसी करते हैं अथवा अब उनके पवेलियन लौटने का वक्त आ गया है। लेकिन एक बात जरूर काबिले गौर है कि गहलोत आसानी से हार मानने वाले नेता नहीं हैं। उनकी जड़े बहुत गहरी हैं। खोखले वृक्ष की तरह उनका धड़ाम से गिरना मुमकिन नहीं लगता।

हमें गहलोत का राजनीतिक भविष्य जानने के लिए अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा...

कॅरिअर आर्किटेक्ट

‘शाला संवाद’ बन रहा विद्यार्थियों का डिजिटल ज्ञान केंद्र

शाला दर्पण पोर्टल से घर बैठे मिल रही गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, ‘टॉक टू टीचर’ सुविधा से दूर हो रही शंकाएं

चुप्पी तोड़

जयपुर। डिजिटल शिक्षा को नई दिशा देने की दिशा में राजस्थान शिक्षा विभाग का शाला दर्पण पोर्टल विद्यार्थियों के लिए एक प्रभावी और उपयोगी मंच बनकर उभरा है। पोर्टल के ‘स्कूल-शाला संवाद’ सेक्शन के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, वीडियो लेक्चर और डिजिटल संसाधन एक ही मंच पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शाला संवाद के तहत विद्यार्थियों को विषयवार वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी एवं आरबीएसई पाठ्यक्रम आधारित ई-कॉन्टेंट, विस्तृत प्रश्न बैंक, दूरदर्शन के शैक्षणिक कार्यक्रमों की सामग्री तथा ई-पत्रिकाओं का लाभ मिल रहा है। इससे कठिन विषयों को सरलता से समझने और परीक्षा की बेहतर तैयारी करने में सहायता मिल रही है। छात्र-छात्राएं लॉगिन कर डिजिटल अध्ययन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।

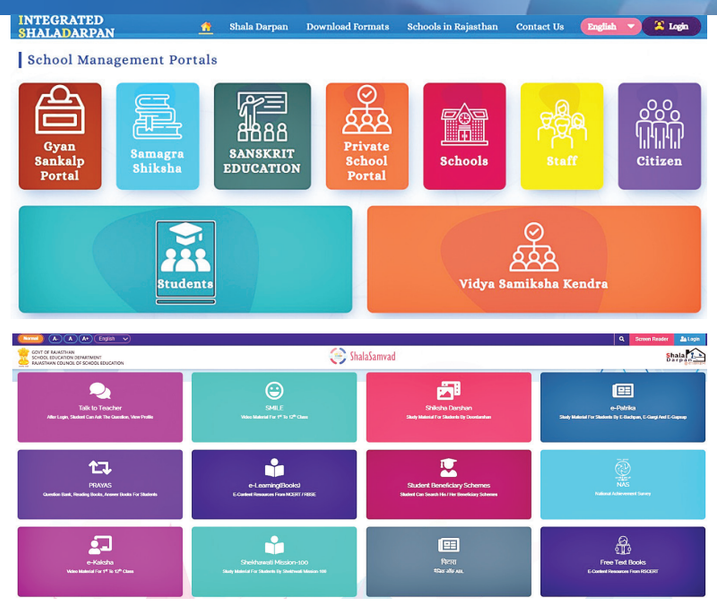

‘टॉक टू टीचर’ से सीधे शिक्षकों से संवाद

पोर्टल की ‘टॉक टू टीचर’ सुविधा विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रही है। इसके माध्यम से छात्र अपनी शैक्षणिक शंकाओं और समस्याओं का समाधान सीधे शिक्षकों से प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है जो कक्षा में अपनी जिज्ञासाएं खुलकर नहीं रख पाते।

ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए बना वरदान

शाला दर्पण पोर्टल ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी शहरों के समान गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध करा रहा है। इससे शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित होने के साथ डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा मिल रहा है।

पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं

- कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री उपलब्ध
- विषयवार वीडियो लेक्चर और ई-कॉन्टेंट
- एनसीईआरटी एवं आरबीएसई आधारित सामग्री
- प्रश्न बैंक एवं ई-पत्रिकाएं
- ‘टॉक टू टीचर’ के माध्यम से शंकाओं का समाधान
- सरकारी शैक्षणिक योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी

शिक्षा विभाग समय-समय पर पोर्टल को अपडेट कर नवीनतम सामग्री उपलब्ध करा रहा है। साथ ही शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बन सके। शाला दर्पण पोर्टल राजस्थान में डिजिटल शिक्षा क्रांति का सशक्त माध्यम बनकर लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा और नई उड़ान दे रहा है।

यूपीएससी की तैयारी में सहायक कुछ सरकारी वेबसाइट

- vikaspedia.in
  Knowledge initiative by InDG.
- makeinindia.com
  Make in India initiative for manufacturing-related info.
- ncert.nic.in
  Download NCERT Texts as PDF.
- nios.ac.in
  Download NIOS Online Materials.
- egyankosh.ac.in
  Download IGNOU Books.
- yojana.gov.in
  Download Yojana and Kurukshetra Magazines.
- upsc.gov.in
  Official Website of UPSC.
- pib.nic.in
  Press Information Bureau Website, for government updates.
- prsindia.org
  PRS Website for tracking bills in Parliament.
- gatewayhouse.in
  Indian Council for Global relations.
- envfor.nic.in
  Ministry of Environment and Forests.
- mea.gov.in
  Ministry of External Affairs.
- indiabudget.gov.in
  Download Budget and Economic Survey.
- ptinews.com
  Press Trust of India.
- ibef.org
  India Brand Equity Foundation for economy and business.
- idsa.in
  IDSA website for Defense and Foreign relations.

किसानों को बड़ी राहत: अब राजस्थान के 26 जिलों में दिन के दो ब्लॉक में मिलेगी बिजली

चित्तौड़गढ़ और टोंक भी योजना में शामिल, वर्ष 2027 तक सभी कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली देने का लक्ष्य

चुप्पी तोड़

जयपुर। राजस्थान में किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के वर्ष 2027 तक सभी कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने की दिशा में अब चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों को भी दो ब्लॉक दिवाकालीन विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय दो ब्लॉक में कृषि बिजली उपलब्ध होने लगी है। सबसे खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ प्रदेश का सर्वाधिक कृषि उपभोक्ताओं वाला जिला है, जहां अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में करीब 1.01 लाख कृषि उपभोक्ता हैं। वहीं, जयपुर डिस्कॉम के टोंक जिले में लगभग 34,748 कृषि उपभोक्ता इस सुविधा से लाभान्वित होंगे।

रात की सिंचाई से मिलेगी राहत

ऊर्जा सचिव एवं डिस्कॉम्स चेयरपर्सन आरती डोगरा ने बताया कि विद्युत वितरण निगमों एवं प्रसारण निगम द्वारा दो ब्लॉक सप्लाई की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। दिन में बिजली उपलब्ध होने से किसानों को अब सर्दी, वर्षा और अन्य विषम परिस्थितियों में रात के समय खेतों में सिंचाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनकी सुरक्षा बढ़ेगी और वे परिवार के साथ अधिक समय भी बिता सकेंगे।

इन 26 जिलों में मिल रही है दिन में बिजली

अजमेर डिस्कॉम के अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनूं, सीकर और चित्तौड़गढ़, जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डीग, भरतपुर, दौसा, करौली और टोंक तथा जोधपुर डिस्कॉम के जालौर, सिरोही और पाली जिले इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

ढाई वर्ष में विद्युत ढांचे को मिली नई मजबूती

दो ब्लॉक सप्लाई को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने विद्युत नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में—

- 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी के 59 नए ग्रिड सब-स्टेशन
- 33 केवी के 444 नए सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले में 132 केवी के 2 तथा 33 केवी के 4 नए जीएसएस स्थापित किए गए हैं, जिससे वहां 563 एमवीए क्षमता बढ़ी है। वहीं टोंक जिले में 33 केवी के 5 नए जीएसएस बनाए गए हैं तथा ट्रांसफॉर्मर क्षमता में 142.40 एमवीए की वृद्धि की गई है।

पीएम कुसुम योजना से मिल रही ताकत

प्रदेश में दो ब्लॉक बिजली आपूर्ति को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य में अब तक 4,338 मेगावाट क्षमता की 1,967 लघु सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें टोंक जिले में 34 मेगावाट तथा चित्तौड़गढ़ जिले में 46 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

- दिन में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी।
- रात में खेतों पर जाने की आवश्यकता कम होगी।
- दुर्घटनाओं और जोखिम में कमी आएगी।
- कृषि उत्पादन और सिंचाई प्रबंधन बेहतर होगा।
- सौर ऊर्जा और मजबूत विद्युत नेटवर्क से आपूर्ति और अधिक विश्वसनीय बनेगी।

राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक सभी कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराना है, जिसके लिए विद्युत ढांचे के विस्तार और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है।

डोर-स्टेप बैंकिंग की ओर अग्रसर राज्य की सहकारी समितियां

पैक्स एवं डेयरी समितियों के माध्यम से ग्रामीणों को घर-घर मिलेगी बैंकिंग सुविधा

चुप्पी तोड़

जयपुर। सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राज्य की ग्रामीण आबादी को उनके घर तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सहकारिता विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। 'सहकार से समृद्धि' अभियान के अंतर्गत राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) एवं प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अब फिनटेक आधारित डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।

डॉ. शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों की टू-डू लिस्ट की समीक्षा करते हुए सभी सक्रिय प्राथमिक डेयरी समितियों को बैंक मित्र बनाकर उन्हें माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि 31 मार्च 2027 तक सभी सक्रिय 12 हजार प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों तथा 30 सितम्बर 2026 तक 5 हजार सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाये जाएं।

शासन सचिव ने बताया कि नाबार्ड की वित्तीय सहायता से पैक्स एवं प्राथमिक डेयरी समितियों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन माइक्रो एटीएम के माध्यम से खातों का बैलेंस जानने, वित्तीय लेन-देन करने, ऋण राशि जारी करने तथा ऋण जमा कराने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब तक लगभग 2 हजार 700 पैक्स तथा बैंक मित्र के रूप में कार्यरत 557 प्राथमिक डेयरी समितियों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों द्वारा अपने एफआईजी पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से पैक्स एवं डेयरी समितियों के व्यवस्थापक ग्रामीणों के निवास अथवा कार्यस्थल पर पहुंचकर उनके खाते खोल सकेंगे तथा जमा संग्रहण कर सकेंगे। इससे ग्रामीणों को अपने घर के निकट ही बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा सहकारी बैंकों की अमानतों में वृद्धि होने से उनकी ऋण वितरण क्षमता भी बढ़ेगी। योजना के तहत ग्रामीणों से जमा संग्रहण पर पैक्स एवं डेयरी समितियों को कमीशन के रूप में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। डॉ. शर्मा ने बताया कि राज्य सहकारी बैंक द्वारा 7 मई को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके बाद प्रदेश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन कर अभियान को गति दी जा रही है। राज्य में 11 हजार 70 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 9 हजार 500 से अधिक ग्राम पंचायतों में पैक्स का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पैक्स स्थापित करना है।

डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने ली हाई-लेवल बैठक

ऑनलाइन आवंटन और नई प्रोसेसिंग यूनिट्स से चमकेगी राजस्थान डेयरी

चुप्पी तोड़

जयपुर। राजस्थान में डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने और पशुपालकों को संबल देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्धाज सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बजट घोषणाओं, लंबित भुगतानों और बुनियादी ढांचे के विकास पर विस्तृत मंथन हुआ।

पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन आवंटन नीति

कैबिनेट मंत्री ने डेयरी नेटवर्क में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े निर्देश दिए। अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इनका आवंटन भी पूरी तरह ऑनलाइन ही होगा।

समितियां स्वयं के खर्च पर लगा सकेंगी बीएमसी: मंत्री कुमावत ने बल्क मिल्क कूलर्स (BMC) के आवंटन की भी समीक्षा की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुधार की जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के तहत अब दुग्ध समितियां अपने स्वयं के पूंजी निवेश से भी बीएमसी स्थापित कर सकेंगी। इससे दूध की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

बुनियादी ढांचे का विस्तार: नए प्लांट्स तैयार: बैठक में राज्य में बनकर तैयार हो चुके नए प्रोसेसिंग और कैटल फीड प्लांट्स के लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्री कुमावत ने बताया कि जयपुर डेयरी में 10 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली एक और नई प्रोसेसिंग यूनिट, राजसमंद में 50 हजार लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट बनकर तैयार है। वहीं, पाली में 300 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला आधुनिक कैटल फीड प्लांट,गुलाबपुरा में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला कैटल फीड प्लांट भी बनकर तैयार हो चुका है। इन नवनिर्मित प्लांट्स के लोकार्पण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। श्री कुमावत ने यह भी बताया कि कोटा में 150 टन प्रतिदिन क्षमता के नए कैटल फीड प्लांट के भूमि पूजन को लेकर भी रणनीति बनाई गई।

भुगतान और योजनाओं की समीक्षा: डेयरी मंत्री ने बजट घोषणाओं को समय पर धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को डेडलाइन तय करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने पशुपालकों और डेयरियों के सभी लंबित भुगतानों को तुरंत निपटाने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री कुमावत ने साफ किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पशुपालकों की आय को बढ़ाना है, जिसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पंच गौरव योजना को गति देने के निर्देश, बजट प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र भेजे जाएं प्रस्ताव: मुख्य सचिव ने की समीक्षा, कहा...

स्थानीय पहचान... रोजगार और आजीविका को मिलेगी नई मजबूती

चुप्पी तोड़

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में पंच गौरव योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी जिलों में इसके प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बजटीय प्रावधानों के अनुरूप प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर राज्य स्तरीय समिति को अनुमोदन के लिए भेजे जाएं, ताकि कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।

बैठक में "एक जिला-एक उत्पाद", "एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति", "एक जिला-एक खेल", "एक जिला-एक पर्यटन स्थल" तथा "एक जिला-एक कृषि उपज" योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों, बजट, प्रगति एवं निगरानी व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि पंच गौरव योजना राजस्थान की विशिष्ट पहचान को सशक्त बनाने, स्थानीय संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ-साथ रोजगार और आजीविका के नए अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सभी विभागों को समन्वित प्रयासों के साथ योजना के उद्देश्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने के निर्देश दिए।

योजना की प्रमुख उपलब्धियां

बैठक में आयोजना विभाग के सचिव रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान—

- एक जिला-एक कृषि उपज योजना के तहत 50 हजार से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया गया।
- एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति योजना के अंतर्गत 85 लाख पौधों का वितरण किया गया।
- एक जिला-एक उत्पाद योजना से जुड़े प्रशिक्षण एवं सेमिनारों में 17 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया।
- एक जिला-एक खेल योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में 25 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने सहभागिता की।
- एक जिला-एक पर्यटन स्थल योजना के अंतर्गत चयनित स्थलों पर 150 से अधिक मेले, उत्सव, स्वच्छता एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्थानीय विकास को मिलेगा बढ़ावा: अधिकारियों ने बताया कि पंच गौरव योजना के माध्यम से हर जिले की विशेष पहचान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे स्थानीय उत्पादों, कृषि उपज, खेल प्रतिभाओं, पर्यटन स्थलों और वनस्पति संसाधनों को नई पहचान मिलने के साथ-साथ रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खेल) प्रवीण गुप्ता सहित वित्त, पर्यटन, कृषि, उद्योग, वन एवं आयोजना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में की विभागीय समीक्षा

राजस्थान को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नंबर वन बनाने का संकल्प

जयपुर (चुप्पी तोड़)। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नंबर वन डेस्टिनेशन बनाने के लिए अधिकारियों को संकल्पित होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पर्यटन परियोजनाएं तय समय-सीमा में पूरी हों, ताकि राजस्थान वैश्विक पर्यटन जगत में अपनी अग्रणी पहचान और मजबूत कर सके।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता तथा राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पर्यटन सचिव शुचि त्यागी, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, पवन जैन, संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा एवं अन्य अधिकारियों की

उपस्थिति में बुधवार को पर्यटन भवन में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की प्रमुख परियोजनाओं और मीडिया प्लान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय में उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग की मीडिया बायिंग रणनीति पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोड शो के माध्यम से राजस्थान पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया।

ड्रिप सिंचाई योजना : बदलते समय में आधुनिक सिंचाई की जरूरत

किसानों के लिए वरदान... 75 प्रतिशत तक मिल रहा अनुदान

चुप्पी तोड़

बहरोड़। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि खेल युवाओं को केवल शारीरिक रूप से सशक्त नहीं बनाते, बल्कि उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, अनुशासन और चुनौतियों का सामना करने का साहस भी विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि खेल और तकनीक दोनों क्षेत्रों में दक्ष युवा ही भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे।

बहरोड़ स्थित आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित समर कैंप-2026 के पुरुष प्रतिभागियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी भी अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बल पर राष्ट्रीय

प्रतिभाओं को निखारने का अभियान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव-2026 युवा प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का व्यापक अभियान है। यहां प्राप्त प्रशिक्षण, अनुभव और आत्मविश्वास प्रतिभागियों को खेलों के साथ-साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा।

एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं। क्षेत्र के अनेक खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धियों से युवाओं के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

खेलों से विकसित होती है नेतृत्व क्षमता

भूपेंद्र यादव ने कहा कि समर कैंप केवल प्रशिक्षण का मंच नहीं, बल्कि सीखने, अनुभव साझा करने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर भी है। उन्होंने कबड्डी, बास्केटबॉल और खो-खो सहित विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभागियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने युवाओं से नियमित अभ्यास, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रयास और समर्पण ही उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

इस अवसर पर नितिन सांगवान, महासिंह चौधरी, बस्तीराम यादव, देशराज खरेरा, मनोज चाचान, मनीष राव सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ली समीक्षा बैठक, सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को दिए विस्तृत दिशा-निर्देश

‘योगा फॉर हैल्दी एजिंग’ थीम पर मनाया जाएगा 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

■ राज्यभर में सुबह 6 से 8 बजे तक होंगे सामूहिक योग कार्यक्रम, पर्यटन स्थलों और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर भी विशेष आयोजन

चुप्पी तोड़

जयपुर। राजस्थान में 21 जून को 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ‘योगा फॉर हैल्दी एजिंग’ थीम के साथ व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य के सभी जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों, राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग दिवस के सफल आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों के सचिव तथा सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

योग संगम पोर्टल पर अधिकतम पंजीकरण का लक्ष्य

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि योग दिवस कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा योग संगम पोर्टल पर अधिकतम संख्या में पंजीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के आयोजन के बाद प्रतिभागियों की संख्या और फोटो भी पोर्टल पर अपलोड किए जाएं, ताकि राज्य की भागीदारी का सटीक रिकॉर्ड तैयार हो सके।

विद्यालय, महाविद्यालय, जेल और पुलिस थानों में भी होंगे कार्यक्रम

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 21 जून को सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों और महाविद्यालयों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके साथ ही चिकित्सा एवं नर्सिंग महाविद्यालयों, कारागृहों तथा पुलिस थानों में भी सामूहिक योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी संबंधित संस्थानों को कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा योग संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए।

नीट परीक्षा के बीच सुरक्षा और समन्वय पर विशेष जोर

बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि योग दिवस के दिन ही नीट परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। ऐसे में जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि दोनों आयोजनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।

नोडल अधिकारियों की होगी नियुक्ति

योग दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी सहभागी विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने तथा समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप योग दिवस को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जाए तथा पिछले वर्ष की तरह इस बार भी राजस्थान को योग दिवस आयोजन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रखा जाए।

पर्यटन स्थलों और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर विशेष आयोजन

मुख्य सचिव ने प्रत्येक जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि स्थानीय नागरिकों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।

मुख्य बिंदु

- 21 जून को मनाया जाएगा 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस।
- इस वर्ष की थीम: ‘योगा फॉर हैल्दी एजिंग’
- सभी जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों और शिक्षण संस्थानों में होंगे कार्यक्रम।
- सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सामूहिक योग सत्र।
- योग संगम पोर्टल पर अधिकतम पंजीकरण और फोटो अपलोड करने के निर्देश।
- चिकित्सा, नर्सिंग महाविद्यालयों, जेलों और पुलिस थानों में भी आयोजन।
- प्रमुख पर्यटन स्थलों और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर विशेष योग कार्यक्रम।
- नीट परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा एवं समन्वय पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक विभाग और जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' 1 जुलाई से

मनरेगा की जगह नई व्यवस्था

राजस्थान को मिलेंगे 11,581 करोड़ रुपए

चुप्पी तोड़

जयपुर। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से देशभर में ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (वीबी-जी राम जी) लागू करने जा रही है। यह नई व्यवस्था वर्तमान मनरेगा की जगह लागू होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका सुरक्षा तथा आधारभूत विकास कार्यों को नई गति देने का दावा किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना हेतु 95,692 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है, जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन माना जा रहा है। राज्यों के अंशदान को शामिल करने पर योजना का कुल आकार 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।

राजस्थान को 11,581 करोड़ रुपए से अधिक की राशिः राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 7,581 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम आवंटन निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा, जिसे आवश्यकता एवं मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।

इस प्रकार प्रदेश में योजना के संचालन के लिए कुल 11,581 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध होगी। यह राजस्थान में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लिए अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय आवंटन माना जा रहा है।

100 नहीं, अब 125 दिन रोजगार की गारंटीः नई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों तक रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यह लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार होंगे।

सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसरों में विस्तार होगा।

रोजगार नहीं तो भत्ता, भुगतान में देरी पर क्षतिपूर्तिः अधिनियम में श्रमिकों के अधिकारों को और मजबूत करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि निर्धारित समयावधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर पात्र व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

इसके अलावा मजदूरी भुगतान में देरी होने की स्थिति में श्रमिकों को क्षतिपूर्ति देने का भी कानूनी प्रावधान किया गया है। इससे रोजगार सुरक्षा और आजीविका संरक्षण को अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद है।

दोहराव रुकेगा, गुणवत्तापूर्ण निर्माण को बढ़ावाः नई व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं में संसाधनों का कन्वर्जेन्स (समन्वय) स्थापित करना, विकास कार्यों में दोहराव रोकना तथा अधिक गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना है।

योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थायी विकास कार्यों को भी बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।

हर सप्ताह मिलेगा भुगतान

योजना में श्रमिकों को समय पर मजदूरी उपलब्ध कराने के लिए भुगतान व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां मजदूरी भुगतान की समय-सीमा 15 दिन थी, वहीं अब साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। मजदूरी की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में जमा होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

जयपुर में CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को मारा थप्पड़, प्रदर्शन के दौरान मचा हंगामा

जयपुर (चुप्पी तोड़)। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के पहले बड़े प्रदर्शन के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही एक युवक ने CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि युवक ने उनके गले में पड़ा तौलिया भी खींचने की कोशिश की। हालांकि इस घटना के बावजूद अभिजीत दीपके बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहे और कार्यक्रम जारी रहा।

घटना के बाद अफरातफरी, लेकिन नहीं रुका प्रदर्शनः थप्पड़ मारने की घटना के बाद कुछ समय के लिए कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने स्थिति को संभाला। इसके बावजूद प्रदर्शन नहीं रुका और जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में युवा जुटे रहे।

युवाओं के मुद्दों को लेकर आयोजित था प्रदर्शनः यह प्रदर्शन NEET समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया था। CJP के इस प्रदर्शन ने राजस्थान की राजनीति और युवा वर्ग के बीच व्यापक चर्चा पैदा कर दी है।

समर्थकों का दावा— आंदोलन को दबाने की कोशिशः घटना के बाद CJP समर्थकों ने इसे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश बताया। समर्थकों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आंदोलन को रोक नहीं सकतीं, बल्कि इससे युवाओं की आवाज और मजबूत होगी।

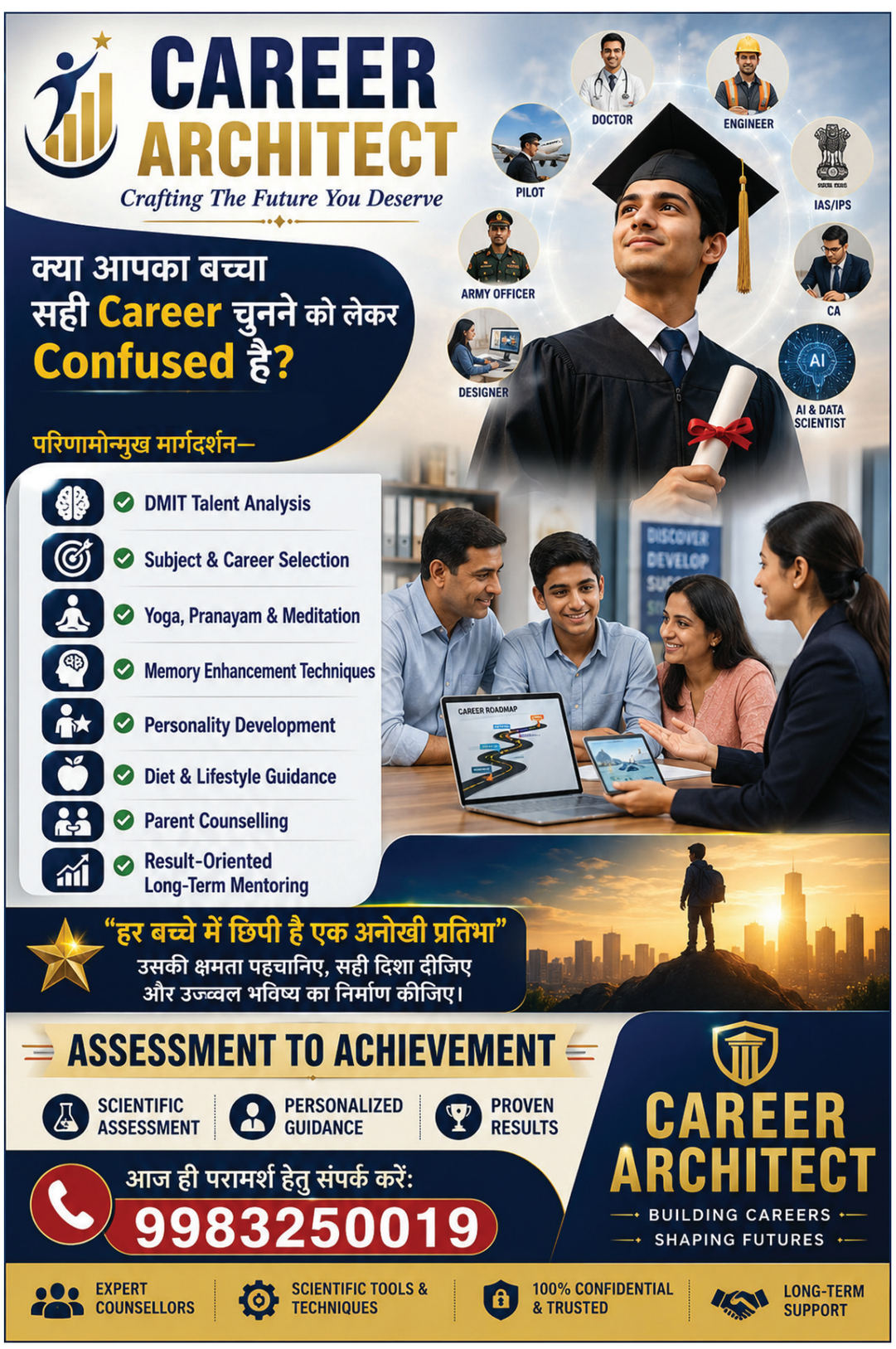

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक शशी कुमार यादव की ओर से महारानी प्रिन्टर्स, 17 मां वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर से मुद्रित तथा ग्राम/पोस्ट बूढ़वाल, तहसील-बहरोड़, जिला अलवर (राज.) 301709 से प्रकाशित। **प्रबंध सम्पादक:** आशा, सम्पर्क सूत्र: +91 8209100941 (किसी भी प्रकार के वाद-विवाद का निपटान क्षेत्र बहरोड़ (अलवर) राज. न्यायालय ही मान्य होगा)